# न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

## (पीठासीन अधिकारी सुनीता डागा, आर0ए0एस0)

अपील संख्या : 35/2015 दायरा दिनांक : 11.02.2015

**उनवान**

जगदीश उम्र 45 साल पुत्र श्री अर्जुनलाल, जाति मीणा, निवासी खानपुरिया, तहसील मांगरोल, जिला बारां

......अपीलांट

**बनाम**

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.....रेस्पोडेट

**बहस हेतु उपस्थिति** :– अभिभाषक अपीलांट – श्री कमलदीप सिंह

अभिभाषक रेस्पोडेंट – पैरोकार सरकार

**निर्णय** **दिनांक : 12.02.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम के तहत न्यायालय जिला कलेक्टर बारां के निर्णय दिनांक 12.11.2014 प्रकरण संख्या 53/2014 से अप्रसन्न होकर प्रस्तुत की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय तहसीलदार मांगरोल के प्रकरण सं0 251/2011 द्वारा अपने निर्णय दिनांक 11.02.2011 से अपीलांट को ग्राम खानपुरिया, तहसील मांगरोल की आराजी खसरा नम्बर 1282 रकबा 0.50 हेक्टर, किस्म गै. मु. बेहड भूमि पर अतिक्रमी मानते हुए 30 दिन के सिविल कारावास की सजा एवं 800/– रूपये शास्ति के दण्ड से दण्डित किया है । इस निर्णय के विरूद्व अपीलांट की प्रथम अपील विद्वान जिला कलेक्टर, बारां द्वारा अपने निर्णय दिनांक 12.11.2014 से खारिज की गई है । इस निर्णय से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभय पक्षीय सुनी गई ।

अपीलांट के द्वारा अपील के साथ धारा–5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया गया । न्यायहित में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डिले कन्डोन की जाती है ।

अपीलांट ने दौराने बहस यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवायी का अवसर नहीं दिया है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का कोई नोटिस नहीं दिया गया है । अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से अपना कब्जा छोड दिया गया है एवं समस्त पैनेल्टी राशि जमा करा दी है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 में प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुसार सजा माफ की है । अतः सिविल कारावास की सजा माफ करने की प्रार्थना की ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रोपर तामील करवायी गयी थी। अपीलांट ने पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जाये ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया । पत्रावली में पटवार मण्डल मऊ की मौका रिपोर्ट दिनांक 04.04.2014 की फोटो प्रति सलंग्न है जिसके अनुसार जगदीश पुत्र अर्जुन लाल, जाति मीणा, निवासी खानपुरिया के जिम्मे सरकार की कोई राशि बकाया नहीं है । प्रार्थी का मौके पर कब्जा नहीं है । अतः कब्जा छोड़ने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा को माफ किया जाना उचित प्रतीत होता है । आर. बी. जे. 2007 (14) पेज 644 यहां चस्पा होती है ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। यदि अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी से कब्जा हटा लिया है तो सिविल कारावास में छूट दी जाती है। लेकिन बेदखली और शास्ति की सजा यथावत रहेगी और यदि अपीलांट द्वारा मौके से कब्जा नहीं हटाया गया है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही समाप्त हो जायेगी, उसके लिए कोई पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी ।

आदेश आज दिनांक 12.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुनीता डागा)<br>
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन<br>
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा